





संपादकीय

ऑनलाइन फरेब

ओनलाइन फरेंट की दुनिया में छाल ही में नया शब्द जुड़ा है डिजिटल गिरफतारी। पहली नजर में विज्ञान कथा जैसा लगने वाला शब्द फिल्माल बास्तविक जीवन के लिये खतरा बनता जा रहा है। वे सरकारी आफद्दे डराने वाले हैं कि इस साल की पहली तिमाही में नागरिकों से इस घोखावधी के जरिये एक अस्व बीस करोड़ की ओनलाइन लूट हुई। बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रवाणनंभी द्वारा इस संकट का जिक्र करने के बाद यह मुद्दा सार्थीय विमर्श में आ गया। उन्होंने देशभासियों से इस भव्य से मुक्त ढाने का अद्यावन किया और कहा कि उहाँ इसमें बचने के लिये सजावता का मंत्र अपनाना है। उड़ानों लोगों से कहा कि वे बचाएं नहीं। साथ ही कहा कि सरकारी एजेंसियां कभी क्लाइंस रेप वा स्काइप आदि माध्यमों के जरिये नागरिकों से संवाद नहीं करती हैं। ये एजेंसिया कभी भी पैसे की मांग नहीं करती हैं। तो जी से पनप रहे इस संकट से बचने के लिये उन्होंने मंत्र दिया कि रुको, सोचो और एकशन लो। दस्तभासल बयांदोइन करके लोगों को लूटने वाले क्लाइंस रेप आदि से कोल करके छारते हैं कि वे पुलिस, सीबीआई, आरकोटिक्स विभाग से बोल रहे हैं। कभी कहा जाता है कि पकड़ी गई नशों की खोप में उनकी मृत्युमिळा है। कहा जाता है कि ड्रास वाले पार्सल जब ढाने के बाद यह सूचना ही जा रही है। उनमें कहा जाता है कि या तो ये मोटी रकम जमा करें या फिर परियाप्त मुगाजनने के लिये तैयार रहें। दस्तभासल, ये शांतिर अपराधी यह दावा करते हैं कि उने जाने वाले व्यक्ति के बारे में वे बहुत कुछ जानते हैं। यह ये अज्ञान के कारण बहुत सारे मोल—माले लोग उनके बिछाए जाल में फँसकर मोटी रकम चुका रहते हैं। यह विडंबना ही है कि नागरिकों को डिजिटली सशक्त करने के लिए मारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सफलता तो पाई लेकिन लोगों को

डॉ. दीपक पात्रोर

सामान्य तौर पर  
जनगणना का उद्देश्य  
सामाजिक विकास के  
उद्देश्यों को व्याप्ति में  
रखा जाता है परन्तु  
लगता है कि केंद्र  
सरकार ने 2025 में छाने  
वाले लोकसभा चुनाव  
को सामने रखकर यह  
फैसला लिया है। 2025  
में जनगणना कराने के  
कारण अगली 2035 में  
छाएगी।

पूरे चार वर्ष के विलम्ब से ही सही, अंतनाल केन्द्र सरकार ने अगले साल यारी 2025 में देश में जननगणना कराने का पैसेला लिया है। यह काम कभी से कम एक वर्ष तक चलेगा और अंकड़ों के परीक्षण, वर्गीकरण एवं अंतिम जनसांख्यिकीय के प्रकाशन में एक और साल लग जाने का अनुमान है। यारी 2026 तक ही यह काम पूरा हो सकेगा। ऐसे लक्ष्य यहीं होगा कि 2028 तक होने वाले परिसीमन तक यह बढ़ा काम पूर्ण हो जाये। सामान्य तौर पर जननगणना का उत्तरेश्य सामाजिक विकास के उत्तरश्यों को व्याप्त में रखा जाता है, परन्तु लगता है कि केन्द्र सरकार ने 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को सामने रखकर यह पैसेला लिया है। 2025 में जननगणना कराने के कारण अगली 2035 में होगी। मारत में 1872 में पहली जननगणना हुई थी जिसे लॉइंड मेयो की देखरेख में करवाया गया था। हालांकि इस गणना का परीक्षण अटिडे हेनरी वाट्टर के अधीन हुआ था इसलिये उन्हें ही आरतीय जननगणना क्षम जननगणना जाता है। ट्रिटिश उपरिवेश होने के कारण मारत में भी दशक की शुरुआत में जननगणना कराने की व्यवस्था हुई। अब

लगभग पूरी दुनिया में जगण्मना का समय यही होता है। इस प्रस्तुति का निवाह करने हुए अवश्यक भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई जो हर साल बढ़ सूख जारी रही। इसके कारण भारत को विश्व पर के देशों द्वारा होने वाली जनगणना के साथ नालंबन करने में सुधिष्ठित होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। आर्थिक जनगणना का प्राप्तम् 1976-77 में हुआ था। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक संस्थान का विश्लेषण करने के लिये होता है। इसमें देश की आर्थिक संस्थाओं के अंकड़े एकत्र किये जाते हैं जो केन्द्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं बनाने में सहायक होते हैं। सम्प्रमुख भारत में 15 बार बिला नागा होने वाली जनगणना को आजाद हिन्दुस्तान में पहली बार 2021 में कोविड-19 के कारण टाला गया था। हालांकि परीस्थितिया 2022 तक ऐसी हो चुकी थी कि जनगणना कराई जा सके लेकिन देश की प्रशासनिकीय अराजकता के लिये यह सुपीट था कि जनगणना न हो। कारोना के कारण लोगों के मरने वालों की संख्या, मृत्यु से प्रमाणित लोग, बेरोजगार आदि की संख्या आरंभ भारत सरकार के पास नहीं है। रोजगार पर हुई एक बहस में

सरकार ने संसद तक में बताया कि उसके पास इसके आंकड़े नहीं हैं। जिनमें भी योजनाएँ चल रही हैं, उनमें हिंतग्राहियों या जरूरतमंदों सम्बंधी तात्पार आंकड़े संटोषास्पद हैं। इसके वरण कोई भी वर्त्यकम जैशानिक आधार पर किया जित नहीं हो सकता है। केन्द्र सरकार ने 2019-20 में अधिक जनगणना तो कराई पर उसका आधार 2011 के ही पुस्तके आंकड़े थे। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के होने विषयों का असर इन आंकड़ों में सच्चाई के साथ परिलक्षित नहीं हुआ है— नोटबनी एवं जीएसटी जिन्होंने मारत के आधिक परिवृद्धि पर बहुत विपरीत प्रभाव छोड़ा था, परन्तु लोगों की वास्तविक वित्तीय स्थिति को कभी उजागर नहीं किया गया। स्पष्टतर ऐसा इन दो कदमों को गलत साधित होने से बचाने के किया गया संसद में भी पहले—पहल इन दोनों विषयों को सकाशतात्काल पहल तो बताया गया पर बाद में उन पर चर्चा बन्त हो गयी। हाल के वर्षों में जनगणना की मांग उठने लगी थी। लास्कर जब से कांग्रेस के नेताओं ने गांधी ने अपनी ही यात्राओं (भारत जोड़ो एवं न्याय यात्रा) में इस ओर लोगों का ध्यान

खींचा था कि भारत में जिस जाति के लोग जिन्हीं सभ्या में हैं, उस परिमाण में उन्हें अवश्यक नहीं मिलते। उन्होंने बार-बार बताया कि केवल सरकार में केवल 5 संघीय ऐसे हैं जो ओवीसी वर्ग से आते हैं। उनके हाथ में कुल बजट का 5 फीसदी भी नहीं हाता। यह विमर्श पहले सुहूल गांधी, फिर कांग्रेस और अंततः विपक्षी गठबन्धन इडिया ने न केवल अपनाया वरन् यह पिछले कुछ विषयानसमा तथा लोकसभा चुनाव का भी प्रमुख सुरा बन गया था। अब पूरा देश चाहता है कि जितिगत जनगणना हो जिससे न केवल आस्पत्र प्रणाली सुधरे बरन् सामाजिक व्याय भी सुनिश्चित हो। हालांकि देखना यह है कि जनगणना में लोगों की जाति व धर्म के आंकड़े किन्तु ईमानदारी से प्रविष्ट होंगे। हालांकि विकास सम्बन्धी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न सत्रों के चुनावों के महेनजर भी जनगणना होती है। पर देखना यह है कि इन्हीं देश से जो मर्दमुश्वासी कर्पार जायेंगी वह किन्तु त्रुटीहीन एवं पारदर्शी होगीय क्योंकि इन आंकड़ों के अधार पर ही मानसिय जनना पार्टी अगले लोकसभा चुनाव के लिये अपनी घूहचना करेगी। न केवल परिसीमन, सहिला आशक्षण, आदि वासी, दलित व अन्ति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को लेकर होने वाली राजनीति आदि को ख्याल में रखकर भाजपा अपनी रणनीति बनायेगी वरन् राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एवं नागरिकता संस्कृत मन जैसे कानूनों के क्रियान्वयन हेतु भी भाजपा अपने लिये रास्ते ढाले ले गी। इनका आधार जनगणना के आंकड़े ही होंगे। इसके मटेनजर विपक्षी दलों एवं सिविल सॉसायटियों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें सरकार द्वारा एकत्र किये जाने वाले आंकड़ों की सटीकता, पारदर्शिता एवं परीक्षण का ख्याल रखने के लिये प्रशासन को जाबदह बनाना होगा। इस बास की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है जिसके पीछे भाजपा की सियासी चक्षा भी छुपी हो सकती है। जनगणना के आंकड़े आईकॉ-सामाजिक विकास का आधार बनें, न कि भाजपा की राजनीति की बुनियाद। 2024 में अपेक्षित बहुमत पाने से बचित रही भाजपा इस जनगणना के बह धर लें ही बड़ा लेल कर सकती है जिस प्रकार से वह देश मर में मनदाता सूचियों और ईशीरण सम्बन्धी ग्राहकों करती है। नागरिकों को चाहिये कि वे सुरु के बारे में सही जानकारी दे न कि मनसनी होने दें।

## जनगणना का बहुप्रतीक्षित फैसला

# बाल विवाह पर बड़ी अदालत का फैसला

हेमलक्ष्मा महाराजे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शजर्यां और फैंडेंट शासित प्रदेशों की सरकारों को सत्त्वन निर्वाचने से देश में बाल विषाह विशेषी अभियानों में भवित्वान्वयिता तो जी आने की अप्रत्याशित गई है। देश की सैकड़ों स्वयंसेवी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप इच्छाकारी बनाने द्वारा कहा है कि बाल विषाह का नाम को प्रभावी नरीकों से लागू करने के भवालाली निर्वाचन से देश से 2030 तक बाल विषाह के खाले के लक्षण को पूरी तरह सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल विषाह के कारण किसी को भी अपनी मर्जी से जीवन साधी बुनें के अधिकार का पूरी तरह से हनन होता है। बच्चों के इस अधिकार को सुनिश्चित करने में जूदा कानून में खालियां हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि बाल विषाह से लास्कर लड़कियों के सामने ज्यादा सुशीलते आ जाती है। ज्यादी के बाद एक नाबालिग लड़की से बच्चों को जन्म देने और प्रजनन क्षमता साबित करने की उमीद की जाती है। बच्चे जो जन्म देने के निर्णय लड़की से छीन लिए जाते हैं। एक बच्चे के रूप में विषाहित महिला की पसंद और स्थायतान का अधिकार बाल विषाह की प्रणाली द्वारा छीन जाता है। बाल विषाह का नाबालिग लड़कियों लिए मजबूर करने से ये तनाव ज्ञालने को मजबूर होती है। गैर-सरकारी संगठन सेवा (सेफ एम्प्लायड बीमें से एसोसिएशन) और सामाजिक कार्यकर्ता निर्बल गोशना की याचिका पर आए इस फैसले का दो सौ से अधिक संस्थाओं के संगठन बाल विषाह मुक्त मारने ते स्थान दिया है। बाल विषाह मुक्त मारन से जुड़ा योलापुर (महाराष्ट्र) की संस्था महाला फुले समाज सेवा मंडल द्वारा के प्रसाद डिस्ट्रिक्ट के मुनाबिक बाल विषाह मुक्त मारन देश के 400 से अधिक जिलों में बाल विषाह के खाले के लिए सक्रिय है। इस गठबंधन से जुड़ी संस्थाओं ने 2023-24 में पूरे देश में 1,20,000 से भी ज्यादा बाल विषाह लक्ष्याए हैं और 50,000 बाल विषाह मुक्त गांव बनाए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति बनोज मिश्र की सांघीयित ने फैसले में कहा है कि श्वाल विषाह प्रतिवेष अधिकानियम (पीसीएमए) 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार व प्रशासन को बचाव-रोकथाम-अभियोजन करनी चाहिए। इसकी उपर्युक्त कार्यान्वयन का लाभित वृद्धिकोण से काम करनी की जरूरत है। अदालत ने स्फूर्ति, धार्मिक संस्थाओं और प्रशासनों तो बाल विषाह से

खिलाफ जागरूकता के प्रसार का अहम जरिया बताते हुए बाल विद्याह बहुल इलाकों में राज्यों को विश्व स्थानीय संगठन की अनुशंसा के अनुरूप सेवाएँ एजुकेशन को स्फूर्ती पाठ्यक्रम में जोड़ने की अनुशंसा की है। इस शिक्षा में लैंगिक समानता, प्रजनन स्थानीय अधिकारों और शारीरिक और मानसिक स्थानीय पर बाल विद्याह के प्रभाव के कानूनी पहलुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी शाखाएँ होनी चाहीए। याचिकाएँ में कहा गया था कि देश में बाल विद्याह की स्थिति गंभीर है और उसके खिलाफ बोर्ड कानून पर अमल नहीं करके उसकी मूल भावना से खिलावड़ किया जा रहा है। इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून नहीं सफल हो सकता है जब बहुसंख्यीय समन्वय हो। कानून प्रयत्नन अधिकारियों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्णय की आवश्यकता है। इस एक बार फिर समुदाय आवासित दृष्टि कोण की जरूरत पर जोर देते हैं। बाल विद्याह एक ऐसा अपराध है जिसने सारे देश को जटकड़ रखा है और इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। साझा प्रयासों से बच्चों के लिए अहिनकर बाल विद्याह जैसी बुझाड़ीयों का पूरी तरह से आत्मा किया जा सकता है। अभियान के कानूनी बुलन्ड यूनिट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले लेने में असफल रही

पूरी दुनिया के लिए नजीब बताते हुए कहा कि यहाँ ऐतिहासिक फैसला सांस्थानिक संकल्प को मजबूती देने की दिशा में निर्णयिक सावित होगा। यह देश से बाल विवाह के समग्र उच्चलन के लाल्य की प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं को दूर करने में बहुत सहायक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिराया है कि उसे बच्चों की फिराया है और अब समय आ गया है कि हम आपां आएं और अब साथ मिलकर इस सामाजिक अभियान का खाला करें। अद्युत वे कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों की सुरक्षा करने में विफल हैं तो फिर जीवन में कोई भी काम गयाने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह अपने मूल रूप में बच्चों से बलात्कार है। बाल विवाह मुक्त भारत से जुड़े संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र एनाडिनीशन विपक्षेट्ट पर अमल कर रहे हैं। जिसमें नीति, संस्थान, समिक्षण, ज्ञान, परिवेश, तकनीक जैसी चीजें शामिल हैं। अभियान को नहत विभिन्न धार्मिक नेताओं और समुदायों को सज्जा प्रयासों से इस अपराध के खाले के लिए 4.90 करोड़ लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि सरकारों ने विलास भर पर्यावरण भैरों

प्रिवेंशन अौफीसर्स नियुक्त करें। इसके लिए कलेक्टर और एसपी भी जाबादेह होंगे। उनके पास उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार और जिम्मेदारी होती जो बाल विवाह करवाने में महत्व देते थे उसे संपन्न करते हैं। अपने सेव्रे में बाल विवाह के मामलों में जानबूझकर कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए डिलाप शल्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यालय की जाए। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को बाल विवाह रोकने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना विकसित करना चाहिए। व्यक्तिगत जाबादेही नय करने और बाल विवाह रोकने के लिए राज्य हर 3 महीने में रिपोर्ट अपलोड करें। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग और गृह संबंधालय इसकी समीक्षा करें। अदालत के मुताबिक स्थानीय लोगों के साथ प्रमाणी सामुदायिक सहभागिना नाकीक विकसित की जाए। राज्यों के गृह संबंधालय स्पेशल जूरियाइल मुलिस यूनिट बनाने पर विचार करें। राज्य स्पेशल चाइलंड ऐरिज प्रोडिविशन यूनिट बनाएं जिसमें पांच सामाजिक कार्यकारियों, जिनमें से दो महिलाएँ हों, को रखा जाए। मजिस्ट्रेट खण्ड संज्ञान लेकर निर्देश जारी कर सकेंगे। केंद्र राज्य सरकारों के साथ विवाह ऐसे समझौते के विरा

**बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही है नियंत्रण रेखा पर भारत-चीन समझौते की सफलता**

अंग्रेजी

हालांकि पूर्वी ललातु की में डेमचोर्क और देपसांग सेंट्रो में संघर्ष और टकराव को लेकर भारतीय और चीन के बीच गतिरोध कम हो गया है। लेकिन तनाव पूरी तरह से समझौते नहीं हुआ है। 22-24 अंतर्राष्ट्रीय रस्स के कठान में जिक्र शिखर सम्मेलन से कुछ छाटे पहले जल्द चाहीं में घोषित किये गये समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बाजाय अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को अधिक आकर्षित करना था। इस समझौते को यह प्रार्थीय तनाव कम करने की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धी के सदर्म में अधिक देखा जाना चाहिए। भारत और चीन के बीच कुछ भूमध्यसे से घोषित किया गया समझौता सीमा विवाद को यासन या में कम करने की तुलना में दिखाए के लिए अदिक है। यह रस्स के कठान में जिक्र शिखर सम्मेलन के सदर्म में था, जिसका उद्देश्य प्रशान्तमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्र पीपुल्स रिपब्लिक निपिंग की बैठक के दौरान होने वाली सहमति के लिए आधार तैयार करना था। चीन का जीतीज वर्क ट्रैक रिकॉर्ड पिछली प्रतिबंदनाओं को अन्वेष्या करने का रहा है। चीन ने चीज़ स्लाइसिंग की रणनीति अपनाई है, यानी छोटे सेंट्रों पर कञ्जा करके फिर से आगे बढ़ जाना। कई सेंट्रों में, चीन ने भारतीय सेंट्रों पर दावा किया है और यहां तक कि बड़े पैमाने पर गांव भी बसाये हैं। उनमें से किसी भी संघर्ष का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। या उस पर समुचित व्यापार भी नहीं दिया गया है। मौजूदा समझौते में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के केंपल



निपटने के लिए कई कदम उठाने होंगे। जब चीन की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से गिर रही थी और कुछ स्ट्रेंग में उसके उद्योग सिकुड़ रहे थे, तब मारत द्वारा चीनी व्यवसायों और मारत में निवेश के खिलाफ उठाये गये कदमों ने उसके हितों को उकसान पहचाना

सुक कर दिया था। समग्र मजबूतियों का आकलन करने के लिए पूरे कदमों और जवाबी कदमों के संदर्भ को ध्यान में रखना होगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख परिचयी देशों द्वारा चीन के नियांत को रोका जा रहा था। यूरोपीय संघ के बाजारों में उच्च टैक्सिफ वाष्ठाओं के साथ चीनी इलेक्ट्रिक बाहों को बाहर रखने की चोकिश की जा रही थी। अमेरिका चीनी ईशी नियांतों के खिलाफ नये कदम उठा रहा था। चीन के पास दुनिया मर में अपने ईशी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा दाव है। इसके अलावा, अमेरिका ने चीनी को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और लक्ष्यों के हस्तानण के खिलाफ पूरी तरह से नाकाम रहा ती है, जिससे कई मायनों में चीनी उद्योगों को पंपु बना दिया है। अमेरिका ने चीन को उच्च अंत औद्योगिक चिप्स की अधूर्ति से बाहर रखा है और यह कम से कम फिलाहाल चीनी उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। चीन स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह दुनिया मर में अपना स्टील डंप कर रहा है। उत्तर यह है कि चीन में हर साल उत्पादित होने वाले स्टील की मात्री मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता नहीं है। कई विकसित देश अपने घरेलू स्टील बाजारों से चीन को बाहर करना चाहते हैं। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी जारी करना बंद कर दिया है। उदाहरण के लिए, चीन के साइंसियों द्वारा ने युवाओं की बोरजगारी के अंकड़े देना बंद कर दिया है, ताकि युवाओं की बड़ी बोरजगारी को छिपाया जा सके।

जा सकते। यह एक ऐसी नीति को आगे बढ़ाने का आदर्श समय था जो संबंधों को सामान्य बनाने की किसी भी प्रक्रिया के लिए चीन को वास्तव में कहीं घोट पहुंचा सकती थी। भारत को चीन से बड़ी दियायांकों के लिए काम करना चाहिए था। यह हमारा समय था जबकि अधिकृत रूप से भारत अब तक चीन की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में था। इसके अलावा, दक्षिण चीन और ताइवान पर अपने कर्मों को लेकर चीन को परिचयी ताक़तों के गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण चीन सामग्र के आसपास खोई भी तटीय देश चीन के साथ नहीं हैं। फिलीपीन्स से लेकर मलेशिया तक के साथ उसके विवाद हैं। कुछ बाधायों में, दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश चीन को संरेह की दृष्टि से देख रहे हैं। लोकिन चीन और भारत दोनों के पास दियावरे के लिए मजबूरियाँ थीं। सिल्ल आतंकवादी की हत्या में कथित संलिपना को लेकर भारत को पश्चिम द्वापा घेया जा रहा था, जिसका नेतृत्व केंद्रों और अंतिक रूप से अभेरिका कर रहा था। चीन को कई मोर्चों पर अभेरिका से आरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बढ़कर, कजान बैठक के मेजबान, रूसी शास्त्रपति ल्यादिसी युतिन ने यूकेन में युद्ध के लिए पश्चिमी देशों के संयुक्त मोर्चे के खिलाफ ताक़त दिखाने की कोशिश की। सऊदी अरब, मिश्र और ईरान के साथ—साथ तुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों की द्वितीय बैठक, रस को अलग-शालग करने में संयुक्त पश्चिमी लॉक की विफलता का प्रदर्शन है।



हॉरर-कॉमेडी जॉनरा के पीछे क्यों पड़े हैं  
लोग? 'भूल भुलैया 3' की

# माधुरी दीक्षित

ने खोला राज

धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 'भूल भुलैया 3' में अहम रोल में नज़र आने वाली हैं। फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार हैं। 'भूल भुलैया 3' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। पिछले कुछ वर्क से हॉरर-कॉमेडी फिल्मों का बाजार तेज़ी से बढ़ा है। ऐसी फिल्में भी खूब बनने लगी हैं। अब माधुरी ने इस बात पर अपनी राय बताई है कि आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग पिछले कुछ वर्क से हॉरर-कॉमेडी जॉनरा की फिल्में बना रहे हैं। हाल ही में माधुरी ने पिंकिला से बात की। इस मौके पर उन्होंने मैट्डक की साल 2018 में

आई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्क्री' की जमकर तारीफ की। इस दौरान माधुरी ने बताया कि उन्होंने अद्वा कपूर और राजकुमार राघव की 'स्क्री 2' अब तक नहीं देखी है, वो कहती है, मैंने स्क्री देखी है, जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने स्क्री 2 नहीं देखी है, पर मैंने सुना है कि ये अच्छी है। इसीलिए तो लोगों ने इस फिल्म को इतना ध्यान दिया है। और ये अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है।

हॉरर फिल्मों के बारे में बात करते हुए माधुरी कहती हैं, मुझे लगता है कि हॉरर फिल्म जुरुआत से बन रही हैं। मुझे याद है मैंने '100 डें' की थी, वो हॉरर फिल्म नहीं थी, लेकिन वो मिस्ट्री ग्लिर जैसी थी, उसमें थोड़ा बहुत हॉरर थी था। अगर मुझे सही याद आ रहा हो तो ज्यादातर हॉरर फिल्में तो रामसे ब्रदर्स ने ही बनाई हैं।

हॉरर फिल्मों पर ज़ोर क्यों?

इस वर्क हॉरर-कॉमेडी जॉनरा के बारे में माधुरी कहती हैं, इस वर्क अच्छा वीएफएक्शन है, इसीलिए ज्यादा लोग ऐसी फिल्में बनाना चाह रहे हैं। वो जिस तरह की सोच दर्शना चाहते हैं और जिस तरह का भूत बनाना चाहते हैं वो अब उससे न्याय कर सकते हैं। कई हॉरर-कॉमेडी फिल्में बनने पर उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास तकनीकी जानकारी है और सोर्टर है, जिससे हम वैसा माहौल बना सकते हैं और रिएलिस्टिक हॉरर इमेजिनेशन को पेश कर सकते हैं। माधुरी का मानना है कि इसीलिए ज्यादा लोग इस जॉनरा में हाथ आजमा रहे हैं।

जानी दुश्मन का किया जित्रा

इस दौरान माधुरी ने राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन का किया जित्रा। उन्होंने कहा, जानी दुश्मन जैसी कुछ ही फिल्में हैं जो बेहद कामयाब रही हैं, जिसमें संजीव कपूर जो नज़र आए थे। कई फिल्में हॉरर स्टाइल में बनी हैं।



# सलमान खान

ने थप्पड़ के सीन से पहले को-एक्ट्रेस को 'धमकाया',  
बोले- थोड़ा भी लगा तो मैं हंगामा मचा दूंगा

सलमान खान की साल 2003 में आई हिट फिल्म 'तेरे नाम' में एकट्रेस इंदिरा कृष्णन ने उनकी लव इंटर्फॉर्न जॉनरा यानी भूमिका चावला की बड़ी बहन का किरदार निभाया था। इंदिरा उस वर्क जॉनी मानी एक्ट्रेस थीं और कई फिल्मों और टीवी सर्वियल्स में काम कर चुकी थीं। फिल्म के एक सीन में उन्हें सलमान को थप्पड़ जड़ा था। इस सीन से पहले

सलमान ने उनके साथ ऐसा प्रैंक (मजाक) किया कि उनके हाथ की कापें लगे थे। इस बात का खलासा खुद इंदिरा ने एक इंटरव्यू में किया है। यूट्यूब चैनल ज्वाइन फिल्म्स से बात करते हुए इंदिरा ने कहा, सलमान ने मेरे साथ एक प्रैंक किया था। उन्होंने मुझसे कहा था 'थोड़ा सा भी लगा ना इंदिरा, तो देखा मैं क्या करता हूं, मैं हंगामा मचा दूंगा।' मैं उनके साथ यो सीन शूट करने से पहले बहुत डर गई थी। जब मुझे उन्हें थप्पड़ मारना था तब मेरे थाथ कापें लगे थे, पर वो बहुत यारे इंसान हैं। उनके साथ काम करने में मुझे बहुत सहज महसूस हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सलमान खान के साथ काम कर रही हूं।

सलमान का स्टाइल हो गया था हिंदू



कि सलमान का हेयरस्टाइल उस दौर में खूब पसंद किया गया था और हर गली में लड़के उनके जैसा ही हेयरस्टाइल किए नज़र आते थे।

तेरे नाम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सलमान खान की कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मैं सलमान और भूमिका के अलावा गवि किशन, सचिन खेडकर, सरफराज का विजयनस किया था।

खान, राधिका चौधरी, दर्शन कुमार और गोपाल दत्त जैसे सितारे नज़र आए थे।

12 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में करीब 20 करोड़ रुपये



आखिरी दौर में है अक्षय कुमार की 'Housefull 5' की शूटिंग, करोड़ों के आलीशान सेट पर शूट होगा क्लाइमेक्स



हिंदी सिनेमा में जब भी कॉमेडी फिल्मों की बात आती है तो अक्सर हाउसफ्लूल फैंचाइजी का भी नाम सामने आता है। 'हाउसफ्लूल' फैंचाइजी की फिल्मों को लेकर लोग दो धंडों में बंट जाते हैं। कई ऐसे हैं, जिन्हें स्लैपस्टिक कॉमेडी जॉनर की ये फिल्में ज्यादा समझ नहीं आती लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें इस फैंचाइजी की पांचवीं फिल्म भी आने वाली है जिसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, हाउसफ्लूल 5 मुंबई में अपने लास्ट शूटिंग शेइयूल के लिए तैयार है, जो आले महीने की शुरुआत में शुरू हो सकता है। खबरों के मुताबिक, यूरोप में क्लूज लाइनर पर 40 दिनों का एक बड़ा शेइयूल शूट किया जा चुका है। अब फिल्म के लीड एक्टर्स अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, मुंबई के विक्रोट सेटों में फिल्म के लास्ट शेइयूल को पूरा कर सकते हैं।

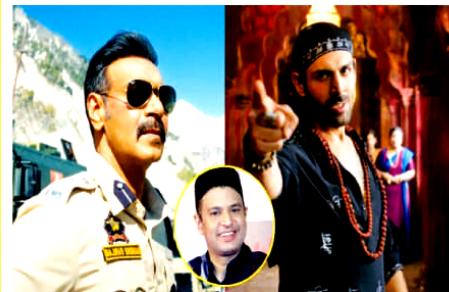
किसमपस तक रेप हो सकता है शूट

ऐसी खबरें हैं कि इस शेइयूल में फिल्म का क्लाइमेक्स और एक भट्टी स्टारर साँग सीक्रीन्स शूट किया जाएगा। मिड डे की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म के इस क्लाइमेक्स के लिए काफी बड़े और लैंबे सेट पीस को तैयार किया गया है, ये सेट एक शानदार और आलीशान बंलों का है, जिसे फिल्म में दिखाया जाएगा। शूट 24 दिन बचे हैं और कहा जा रहा है कि किसमपस तक फिल्म बनाने पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

अपने सींस स्टूट करेंगे संजय दत्त और जैकी श्रॉफ

बात करेंगे फिल्म की स्टारकास्ट की तो हाउसफ्लूल फैंचाइजी को बैंसे भी अपनी बड़ी स्टारकास्ट के लिए जाना जाता है। इस बार भी फिल्म में एक साथ काफी सारे सितारे नज़र आने वाले हैं। खबरों की मानें तो सजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी जल्द ही फिल्म की कास्ट को ज्वाइन करेंगे, दोनों ही सितारों वोजा इश्वर के बजह से यूके में अपने सीन को शूट नहीं कर पाए थे और अब वो फिल्म का अपना पार्ट मुंबई में शूट करेंगे।

Singham Again vs Bhool Bhulaiyaa 3 का खेल हुआ और गंदा, टी-सीरीज की स्ट्राइक के बाद हटाना पड़ा 'सिंघम अगेन' का टाइटल ट्रैक!



Singham Again और Bhool Bhulaiyaa 3 एक ही दिन रिलीज हो रही हैं, दोनों फिल्मों के बीच कई टक्कर की उमीद है, कुछ दिन पहले दोनों फिल्मों के बीच स्क्रीन वारं चल रहा था। कौपीटीशन इस बात का था, कौन-सी फिल्म ज्यादा शोज और सत्रीन्स हथियाएंगी। फिल्महाल इस मामले में 'सिंघम अगेन' मरटीज्वेस्म में आगे बढ़ाई जा रही है और 'भूल भुलैया 3' सिंघम स्पॉन्स पर। अभी ये घमासान खत्म ही हुआ था कि एक और गेम सामने आ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि टी-सीरीज ने 'सिंघम अगेन' के टाइटल ट्रैक पर कौपीराइट स्ट्राइक मार दी। इसके चलते ये गाना यूट्यूब से हटाना पड़ा है। हालांकि इसे दोबारा अपलोड किए गए गए गाने में 'सिंघम' वाली मैन ट्रॉन को हटा दिया गया है। दोबारा अपलोड किए गए गाने में 'सिंघम' वाली मैन ट्रॉन को हटा दिया गया है। 'सिंघम' के थीम म्यूजिक की जगह एक नए म्यूजिक को जोड़ा गया है। यहां ये जानना जरूरी है कि 'भूल भुलैया 3' की प्रोइड्यूसर टी-सीरीज है।

टी-सीरीज ने स्ट्राइक मारी क्यों?

दरअसल 'सिंघम' और 'सिंघम रिटर्न्स' के सभी गाने टी-सीरीज ने रिलीज किए थे, यानी इन दोनों फिल्मों के म्यूजिक राइट्स भूषण कुमार की कंपनी के पास होंगे। रोहिंग शेट्री ने ये राइट्स खरीदे नहीं होंगे, और 'सिंघम' वाले म्यूजिक को इस्तेमाल कर लिया होगा। इसीलिए ही टी-सीरीज ने टाइटल ट्रैक पर कौपीराइट स्ट्राइक मार दी। इस बजह से सारेगामा को गाना हटाना पड़ा। हालांकि 'सिंघम अगेन' के ट्रैलर में कहीं पर भी 'सिंघम' के थीम म्यूजिक का ट्रैलर में इसे क्यों यूज किया।

किसकी गलती है?

पहली बात तो 'सिंघम अगेन' की टीम को बिना परमिशन के म्यूजिक उठाना नहीं चाहिए था। उठाया भी था, तो 'टी-सीरीज' को थोड़ा नैतिकता दिखानी चाहिए था। लोग कह रह





